Newspaper Clips

October 20, 2012

Dainik Bhasker ND
20/10/2012 P-11

आईआईटी-जेईई के लिए बोर्ड ने जारी किए कट ऑफ मार्क्स

भास्कर न्यूज | अजमेर

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के निर्देशानुसार आईआईटी जेईई परीक्षा के लिए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा निर्धारित 20 पर्सेंटाइल फार्मूले के अनुरूप वर्ष 2012 की मुख्य परीक्षा के परिणामों के आधार पर कट ऑफ मार्क्स की घोषणा की है।

वर्ष 2012 की परीक्षा के आधार पर 20 पर्सेंटाइल के दायरे में आने के लिए सामान्य श्रेणी के परीक्षार्थियों का कट ऑफ मार्क्स 331 (66.20 प्रतिशत), अनुसूचित जाति के लिए 315 (63.00 प्रतिशत), अनुसूचित जनजाति के लिए 309 (61.80 प्रतिशत) और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 327 (65.40 प्रतिशत) अंक निर्धारित किए गए हैं लेकिन जेईई 2013 में प्रविष्ट होने के लिए राजस्थान बोर्ड के परीक्षार्थियों के लिए मुख्य परीक्षा 2013 का परीक्षा परिणाम आधार होगा। वर्ष 2013 की मुख्य परीक्षा के परीक्षार्थियों में से आईआईटी-जेईई 2013 के लिए प्रविष्ट होने वाले 20 पर्सेंटाइल अभ्यार्थियों की गणना सीबीएसई द्वारा निर्धारित इस फार्मूले से की जाएगी। सीबीएसई के निर्देशानुसार वर्ष 2013 की जेईई परीक्षा में पात्रता के लिए बोर्ड की ओर से आयोजित वर्ष 2011 एवं 2012 की परीक्षाओं में गणित विषय सहित उत्तीर्ण विज्ञान वर्ग के परीक्षार्थियों को परिणाम सुधार का विशेष अवसर प्रदान किया जा रहा है।

Tribune ND 20/10/2012 P-2

Sibal bats for privatisation in higher education

ADITI TANDON/TNS

NEW DELHI, OCTOBER 19

Human Resource Development Minister Kapil Sibal today made a strong case for private participation in the education sector, saying the government did not have the financial muscle to create universities that would be required in the future to accommodate all youngsters.

By 2030, close to 400 million youth would be seeking college education. For that to happen, India would require at least 800 more universities and 40,000 more colleges.

Even today, as against 140 million 18 to 23 year olds, only 20 million are in colleges.

Interacting with mediapersons on the sidelines of the India-New Zealand Education Council meeting at Vigyan Bhavan today, Sibal said the country was well on track to achieve the goal of 30 per cent gross enrollment ratio (GER) - number of class-XII pass outs who enter colleges - in higher education but the government was not in a position to create the infrastructure needed to accommodate the rising number of education seeking population.

"Our GER will be 30 per cent by 2020 and by 2030 close to 400 million people will be going to universities. Either massive expansion needs to be done or new universities will be required. The government cannot fulfil this requirement and we need to open doors to the private sector," Sibal said, raising the pitch for privatisation of the general education sector on the lines of medical education. India's current GER is 15 per cent.

The minister also appealed to the Opposition parties to aid the passage of the pending higher education reform Bills, many of which seek to regulate private operators to ensure the delivery of quality education.

"We want our Bills to pass in Parliament so that the private sector should get a chance to help. The private sector, however, needs to be regulated. So we need the National Accreditation Authority Bill and the Prohibition of Educational Malpractices Bill. I hope we get support from the Opposition in the Winter Session of Parliament for these Bills," Sibal said.

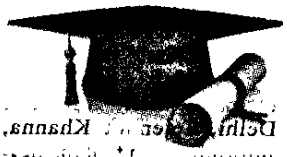

"By 2030 close to 400 million people will be going to universities. Either massive expansion needs to be done or new universities will be required. The government cannot fulfil this requirement and we need to open doors to the private sector"

— Kapil Sibal, HRD Minister

'AAKASH' FOR ALL

Budget tablet "Aakash" will be provided to every student in the next five years. The technology will enable one teacher to teach 10,000 children at one time. Each village will be connected with fiber optics by December, 2013. So lectures will become possible, Sibal said.

Hindustan Times ND 20/10/2012
P-10

Beware of fake agents, UK tells Indian students

Charu Sudan Kasturi
charu.kasturi@hindustantimes.com

NEW DELHI: Indian students applying to study in the UK should stay clear of "unscrupulous agents" who are using increasingly varied strategies to dupe applicants, the UK Border Agency (UKBA) has warned.

The UKBA — Britain's immigration authority — has also decided to bar agents from collecting passports and other documents on behalf of applicants at the end of visa processing, from October 10.

"The UKBA wants to ensure the safe and secure return of documents to visa applicants," a British High Commission official told HT.

Thousands of Indian students each year find themselves trapped in a complex web of misleading agents, poor regulations and dubious universities that leaves them in debt, and often on the wrong side of the law in a foreign land, as reported by HT in a three-part series earlier this week.

After the US, the UK draws most Indian students, followed by Australia and Canada. For some, the journey begins with attempting to lie to immigration authorities while seeking a visa.

"Don't be misled by unscrupulous agents and think that it is acceptable to submit forged documents," UKBA regional director Thomas Greig said. Applicants caught for using forged documents are barred for 10 years from applying.

From claiming that they have contacts within the UKBA, the British High Commission or VFS-Global, its commercial partner, to pointing applicants to fake websites designed to look official, agents are using increasingly complex strategies, the UKBA has warned.

The new warning by UK authorities comes at a time when new visa rules have drastically cut student applications to that country by 30%. But British authorities have in recent years also come across increasing instances of visa fraud from Indian applicants.

FOR FULL STORY, GO TO
hindustantimes.com/indianstudents

THE RED FLAGS

- Agents who claim to know someone in the UK High Commission, UKBA or VFS Global, their commercial partner.
- Agents who claim they can speed up visa process in exchange for a fee.
- Agents who suggest they can help submit fake documents.
- Fake sites designed to look like official or VFS websites.

SOURCE: UK BORDER AGENCY

Veer Arjun ND 20/10/2012 P12

शिक्षा क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और न्यूजीलैंड ने किए करार

विशेष संवाददाता

नई दिल्ली। भारत और न्यूजीलैंड ने आज अपने अलग अलग शिक्षण संस्थानो के बीच सहयोग के लिहाज से छह सहमति पत्रों (एमओयू) पर दस्तखत किये।

जब तक इन विधेयकों को संसद में मंजूरी नहीं मिलती तब तक निजी और विदेशी संस्थानों से भारत में विवि व कॉलेज स्थापित करने संबंधी बात सिरे नहीं चढ़ सकती

केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल और न्यूजीलैंड के उच्च शिक्षा, रोजमार मंत्री स्टीवन जोयके ने आज यहां भारत-न्यूजीलैंड शिक्षा परिषद की पहली बैठक की सह-अध्यक्षता की। मानव संसाधन विकास मंत्रालय की विज्ञप्ति के अनुसार बैठक के दौरान दोनो नेताओं ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग और साझेदारी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। दोनों देशों ने परिषद द्वारा तैयार विशेष कार्यक्रमों के माध्यम से सहयोगी गतिविधियों को बढ़ाने के लिए दस लाख अमेरिकी डालर आवंटित करने की भी प्रतिबद्धता दोहराई। दोनो देशो के बीच जो एमओयू हुए है उनमें दोनों देशों के खेल मंत्रालयों के बीच खेलों के क्षेत्र में सहयोग के लिए, दिल्ली विश्वविद्यालय और मैसी यूनिवर्सिटी-न्यूजीलैंड के बीच और इनू तथा न्यूजीलैंड की ओपन पॉलीटेक्निक के बीच साझेदारी के लिए करारनामों पर दस्तखत किये गये। जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय और वेलिंगटन की विक्टोरिया यूनिवर्सिटी के बीच, पंजाब तकनीकी विश्वविद्यालय और न्यूजीलैंड के वइयारिकी इस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के बीच भी विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के लिए सहमति हुई। दिल्ली विश्वविद्यालय और लिंकन यूनिवर्सिटी-एशिया पेसिफिक फुटबॉल एकैडमी के बीच भी एक एमओयू किया गया है। प्रमुख विधेयकों के लंबित रहते उच्च शिक्षा के क्षेत्र में क्षमता विस्तार हासिल न कर पाने की मजबूरी समझाते हुए सरकार ने आज उम्मीद जताई कि विपक्ष संसद के शीतकालीन सत्र में इन विधेयकों के पारित होने में मदद करेगा। मानव ससाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल ने कहा कि जब तक इन विधेयकों को संसद में मंजूरी नहीं मिलती तब तक निजी और विदेशी संस्थानों से भारत में विश्वविद्यालय और कॉलेज स्थापित करने संबंधी बात सिरे नहीं चढ़ सकती।

भारत और न्यूजीलैंड की एजुकेशन काउंसिल मीटिंग को नई दिल्ली में सम्बोधित करते हुए मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल।

National Duniya ND 20/10/2012 P16

नई तकनीक के जरिए 'हवा से बनेगा पेट्रोल'

लंदन (भाषा)। ब्रिटेन की एक छोटी सी कंपनी ने एक ऐसी नई क्रांतिकारी तकनीक विकसित करने का दावा किया है जिससे मात्र हवा और बिजली के इस्तेमाल से पेट्रोल का उत्पादन किया जा सकेगा। उत्तरी इंग्लैंड में एक कंपनी ने 'एयर कैप्चर' तकनीक विकसित की है जिसमें कृत्रिम पेट्रोल बनाया जा सकेगा।

इस क्षेत्र के विशेषज्ञों का कहना है कि यह एक ऐसी तकनीक है जो जलवायु परिवर्तन के खिलाफ पूरे अभियान की रूपरेखा बदल देगी और दुनिया के ऊर्जा संकट का नया समाधान पेश करेगी। इस सप्ताह लंदन में एक इंजीनियरिंग सम्मेलन में पेश की गई यह तकनीक वातावरण से कार्बन डाइआक्साइड हटाकर काम करती है। दी टेलीग्राफ में यह रिपोर्ट प्रकाशित हुई है। इस तकनीक में सोडियम हाइड्रोआक्साइड को लेकर उसे कार्बन डाइआक्साइड से मिलाया जाता है और उसके बाद सोडियम कॉर्बोनेट का

'विद्युतीकरण' किया जाता है जिससे बाद में जाकर शुद्ध कार्बन डाइ आक्साइड पैदा होती है। इसके बाद जलकणों के विद्युतीकरण से हाइड्रोजन पैदा की जाती है।

यह तकनीक एयर फ्यूएल सिंडिकेशन ने विकसित की है। कंपनी के अधिकारियों ने इस तकनीक का इस्तेमाल करते हुए स्टोकेटोन टीस में एक छोटी रिफाइनरी से तीन महीने में पांच लीटर पेट्रोल उत्पादित करने का दावा किया है।